>

Title: Need to take action against a police officer for his conduct in Rewa Parliamentary Constituency of Madhya Pradesh.

श्री देवराज सिंह पटेल (रीवा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्रालय का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। 22 नवम्बर 2012 को एक साधारण दुर्घटना में मेरे लोक सभा क्षेत्र रीवा के एक युवा तेज प्रताप सिंह के ऊपर रीवा संभाग के आईजी श्री गांजीराम मीणा के दबाव पर सिविल लाइन रीवा थाने में गांजा का जबरन झूठा मुकदमा दायर करके नारकॉटिक्स एक्ट लगाकर उनको जेल भेज दिया गया। घटना 22 नवम्बर 2012 की है। सुबह दस बजे तेज प्रताप सिंह आई जी के बंगले के सामने से गुजर रहे थे तभी दो मोटरसाइकिल सवाल उनसे टकरा गये। उनमें से एक जो आईजी मीणा जी के घर में रहने वाला सिपाही था और दूसरा पशु चिकित्सालय में एक कम्पाउंडर था। तभी यह युवा इनको उठाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसी समय आईजी श्री मीणा बाहर निकले और तेज प्रताप सिंह पर गाली गलौच करते हुए पुलिस बुलाते हुए पद का दुरुपयोग करते हुए यह कहकर उनको जेल भिजवा दिया कि इसके ऊपर ऐसा गांजा चरस का मुकदमा लगाओ कि इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और गांजा रखने के जुर्म में फर्जी मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया गया तथा छोड़ने की शर्त पर आईजी श्री मीणा ने इनके पिता शैलेन्द्र भानसिंह जो हार्ट के मरीज हैं, उनसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिये।

महोदय, मैं सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पुलिस महानिरीक्षक का पद संभाग के सबसे बड़े पद को अलंकृत करता है जिनका कार्यक्षेत्र जनता के साथ बड़ी ही पारदर्शिता का होता है। लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि मध्य प्रदेश सरकार के संरक्षण प्राप्त होने के कारण नियम कायदों को तोड़कर डाकुओं का फर्जी एनकाउंटर व हत्या कराना, गलत मुकदमों में फंसाकर जेल भेजना आएदिन की इनकी ये घटना है। श्री मीणा के विरुद्ध वर्तमान समय में पत्राचार के माध्यम से मैंने इनके कारनामों को उजागर किया है जो भारत सरकार से लेकर मध्य प्रदेश सरकार तक विचाराधीन हैं और आज उजागर करने से माननीय सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज जो मैंने सदन में यह बात उजागर की है, मुझे डर है कि मुझ पर भी या मेरे परिवार और मेरे लोगों पर भी ये मीणा साहब नॉरकोटिक्स एक्ट लगा सकते हैं क्योंकि इनको सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अविलम्ब कार्रवाई की मांग करता हूं जिससे रीवा संसदीय क्षेत्र के जनमानस को राहत मिल सके।